भारत में जेन–जी आंदोलन और उसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव

DR. DHIRAJ BAKOLIA

Professor, Department of Political Science, Govt. Lohia College, Churu (Raj.)

सार

भारत में जेन–जी (Gen Z) आंदोलन 2026 में मुख्य रूप से बढ़ती बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ सड़कों पर उभरा है। [1, 2, 3]

जेन–जी आंदोलन के प्रमुख कारण

- रोजगार और बेरोजगारी का संकट: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, देश में स्नातक बेरोजगारी दर काफी अधिक है और युवा वर्ग काम की तलाश में संघर्ष कर रहा है। [1, 2]
- परीक्षाओं में अनियमितताएँ: राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल और कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में धांधली तथा पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों और युवाओं में भारी रोष फैला। [1, 2]
- कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का उदय: मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के बाद युवाओं ने व्यंग्यात्मक रूप से 'कॉकरोच जनता पार्टी' का गठन किया, जिसने सोशल मीडिया और मीम्स के जरिए इस विरोध को संगठित किया। [1]
- चुनावी और संस्थागत पारदर्शिता की मांग: सितंबर 2026 में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए चुनाव आयोग (ECI) में आंतरिक असहमति और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों के बाद यह आंदोलन विपक्षी दलों के साथ जुड़कर और व्यापक हो गया।

भारतीय राजनीति पर प्रभाव

- शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: जुलाई 2026 में, मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की गड़बड़ी और देशव्यापी विरोध के दबाव के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2014 के बाद मोदी कैबिनेट में यह पहला ऐसा इस्तीफा था। [1, 2]
- पारंपरिक राजनीति की चुनौती: यह आंदोलन दिखाता है कि युवा अब केवल पारंपरिक चुनावी वादों से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि वे संवाद, सीधी भागीदारी और तत्काल जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। [1]
- राजनीतिक समीकरणों में बदलाव: इस आंदोलन में मध्यमवर्गीय और हिंदू–राष्ट्रवादी माने जाने वाले युवा भी शामिल हुए हैं, जिससे यह धारणा टूटी है कि युवा वर्ग एकतरफा रूप से किसी एक राजनीतिक दल के साथ स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है। [1]
- सरकार और सुरक्षा बलों का कड़ा रुख: दिल्ली के केंद्रीय इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती, इंटरनेट बंद करने और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की घटनाओं पर मानवाधिकार एजेंसियों और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। [1, 2]

परिचय

राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (NEET) में कथित अनियमितताओं, बढ़ती स्नातक बेरोज़गारी और शिक्षा के बढ़ते वित्तीय बोझ को लेकर व्यंग्यात्मक किंतु प्रभावशाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जेन ज़ी के नेतृत्व वाले विभिन्न विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं।

बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया और पेरू में जेन ज़ी के नेतृत्व वाले राजनीतिक आंदोलनों से वैश्विक तुलना करते हुए, इन विरोध प्रदर्शनों ने युवाओं की आकांक्षाओं, नागरिक भागीदारी और अधिक जवाबदेही तथा प्रणालीगत सुधारों की मांगों को सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

जेन ज़ी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन भारत और वैश्विक स्तर पर एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरे हैं, जो परीक्षा की निष्पक्षता, युवा बेरोज़गारी, बढ़ती शिक्षा की लागत तथा लोकतांत्रिक भागीदारी से संबंधित चिंताओं को उजागर करते हुए राजनीतिक लामबंदी की प्रकृति को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं।

युवाओं के मोहभंग को दूर करने के लिये शिक्षा, रोज़गार, परीक्षा प्रशासन, मानसिक स्वास्थ्य और युवा भागीदारी के क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, ताकि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को एक सतत युवा लाभांश में परिवर्तित किया जा सके।

जेन ज़ी: इसे "ज़ूमर्स" के नाम से भी जाना जाता है। यह वह जनसांख्यिकीय समूह है जो मिलेनियल्स के बाद और जनरेशन अल्फा से पहले आता है।[1,2,3]

इसमें व्यापक रूप से वर्ष 1990 के मध्य से लेकर वर्ष 2010 के प्रारंभ तक जन्म लेने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं और इसकी विशेषता डिजिटल नेटिविटी, सोशल मीडिया सहभागिता तथा नागरिक एवं राजनीतिक जागरूकता है।

राजनीति में भूमिका: जेन ज़ी एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है, जो भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, असमानता और शासन संबंधी विफलताओं के विरुद्ध सोशल मीडिया के माध्यम से संगठित होकर सक्रिय भूमिका निभा रही है।

पारंपरिक राजनीतिक आंदोलनों के विपरीत, ये विरोध प्रदर्शन विकेंद्रीकृत, डिजिटल रूप से समन्वित और युवाओं द्वारा संचालित होते हैं।

विभिन्न देशों ने निरंतर युवा लामबंदी के कारण नीतिगत बदलाव, सरकारों में परिवर्तन और राजनीतिक सुधार देखे हैं।

वैचारिक राजनीति (1950–1960 का दशक): युवा आंदोलन मुख्य रूप से परिसरों तक सीमित थे और इन्हें SFI (स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) तथा ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) जैसे वामपंथी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों द्वारा आकार दिया गया।

प्रमुख चिंताओं में भाषा, शिक्षा और वैचारिक लामबंदी शामिल थीं।

प्रमुख घटनाक्रम:

तमिलनाडु में हिंदी-विरोधी आंदोलन (1965)।[4,5,6]

नक्सलबाड़ी आंदोलन (1967): मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा से प्रभावित यह आंदोलन सक्रिय छात्र भागीदारी से संबंधित था।

सत्ता-विरोधी और लोकतांत्रिक लामबंदी (1970 का दशक): छात्र आंदोलनों ने परिसरों से बाहर विस्तार किया और भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति तथा निरंकुश शासन को चुनौती दी।

प्रमुख घटनाक्रम:

गुजरात में नव निर्माण आंदोलन (1974)।

जयप्रकाश नारायण (JP) आंदोलन (1974–75): भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध आंदोलन।

छात्र लामबंदी ने आपातकाल (1975–77) से पूर्व की राजनीतिक घटनाओं में योगदान दिया।

पहचान, क्षेत्रवाद और सामाजिक न्याय (1980–1990 का दशक): युवा आंदोलन तेज़ी से क्षेत्रीय पहचान, प्रवासन और सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) से संबंधित मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित होने लगे।

प्रमुख घटनाक्रम:

असम आंदोलन (1979–85): अखिल असम छात्र संघ (AASU) के नेतृत्व में चलाया गया, जिसका समापन असम समझौते (1985) के रूप में हुआ।

मंडल आयोग विरोधी प्रदर्शन (1990): सार्वजनिक रोज़गार और शिक्षा में आरक्षण के मुद्दे को लेकर।

अधिकार-आधारित सक्रियता (वर्ष 2000–2010 का दशक): इंटरनेट और सोशल मीडिया के विस्तार ने युवा सक्रियता को पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नागरिक अधिकारों की दिशा में परिवर्तित कर दिया।

प्रमुख घटनाक्रम:

अन्ना हज़ारे आंदोलन (2011): जिसे लोकप्रिय रूप से इंडिया अगेंस्ट करप्शन (IAC) आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसमें भ्रष्टाचार से निपटने के लिये जन लोकपाल बिल की मांग करते हुए लाखों युवाओं को लामबंद किया गया।

निर्भया विरोध प्रदर्शन (2012): इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित आपराधिक कानूनों में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए और लैंगिक न्याय की मांग में युवाओं की भूमिका देखने को मिली है।

जेन ज़ी और मुद्दा-आधारित सक्रियता (वर्ष 2020 के दशक से वर्तमान तक): समकालीन युवा आंदोलन डिजिटल रूप से संचालित, विकेंद्रीकृत और शिक्षा, रोज़गार, शासन तथा सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हैं।[7,8,9]

प्रमुख घटनाक्रमः

CAA/NRC विरोधी परिसर प्रदर्शन (2019–20)।

अग्निपथ के लिये विरोध प्रदर्शन (2022)।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलन (2026): कथित NEET पेपर लीक, बेरोज़गारी और शिक्षा की बढ़ती लागत को लेकर।

युवा आंदोलनों में प्रमुख परिवर्तन

करिश्माई नेतृत्व से विकेंद्रीकृत नेटवर्क की ओरः आंदोलनों का स्वरूप जयप्रकाश नारायण एवं अन्ना हज़ारे जैसे व्यक्तित्व-केंद्रित नेतृत्व वाले आंदोलनों से विकसित होकर नेतृत्व-विहीन, डिजिटल रूप से समन्वित अभियानों में परिवर्तित हो गया है।

विचारधारा से मुद्दा-आधारित सक्रियता की ओरः ध्यान अब वैचारिक राजनीति से हटकर शिक्षा सुधार, परीक्षा प्रणाली की अखंडता, बेरोज़गारी, जलवायु कार्रवाई एवं गिग इकॉनमी के अधिकारों जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर केंद्रित हो गया है।

राजनीतिक दलों से संबद्धता से स्वतंत्र लामबंदी की ओरः हाल के अनेक आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक दलों से बाहर संचालित हो रहे हैं तथा समर्थन जुटाने के लिये डिजिटल व्यंग्य, मीम्स एवं ऑनलाइन अभियानों पर निर्भर हैं।

भौतिक से हाइब्रिड विरोध-प्रदर्शन मॉडल की ओरः जहाँ पहले लामबंदी (Mobilisation) लंबे समय तक चलने वाले सड़क अभियानों पर निर्भर करती थी, वहीं आधुनिक आंदोलन सोशल मीडिया सक्रियता एवं ज़मीनी प्रदर्शनों को संयोजित करते हैं, जिससे तीव्र एवं व्यापक स्तर पर जन लामबंदी संभव हो पाती है।

परिसर संबंधी मुद्दों से राष्ट्रीय नीति-विमर्श की ओरः आज के युवा आंदोलन शिक्षा नीति, रोज़गार, शासन, लोकतांत्रिक जवाबदेही एवं संस्थागत सुधारों से संबंधित विमर्शों को तेज़ी से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे वे सार्वजनिक नीति-निर्माण के महत्त्वपूर्ण भागीदार बन गए हैं।

भारत में युवाओं के मोहभंग (Youth Disillusionment) के अंतर्निहित कारण क्या हैं?

समष्टि आर्थिक असमानताएँः "शिक्षित बेरोज़गार" [10,11,12]

रोज़गार-विहीन विकास एवं कौशल असंगतिः भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, किंतु यह युवा जनसंख्या वृद्धि को समाहित करने के लिये आवश्यक गति से औपचारिक एवं पर्याप्त पारिश्रमिक वाले रोज़गार सृजन करने में असफल हो रही है।

ILO इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ने एक चिंताजनक वास्तविकता को रेखांकित किया हैः भारत के बेरोज़गार कार्यबल में युवाओं की हिस्सेदारी 83% है।

इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि स्नातकों में बेरोज़गारी दर 29.1% है, जो बिना किसी औपचारिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की बेरोज़गारी दर (3.4%) की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं स्वचालन (Automation) के तीव्र प्रसार से प्रवेश-स्तरीय एवं नियमित प्रकृति के रोज़गार भी प्रभावित हो रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 9.2 करोड़ रोज़गार विस्थापित हो सकते हैं, यद्यपि इसी अवधि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित नवीन रोज़गार अवसरों का भी सृजन होगा। यह स्थिति बड़े पैमाने पर पुनःकौशल (Reskilling) एवं कौशल उन्नयन (Upskilling) की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करती है।

औपचारिक क्षेत्र का अनौपचारिकीकरणः सृजित हो रहे सीमित रोज़गारों का एक बड़ा भाग अस्थिर "गिग इकॉनमी" में केंद्रित है।

यह युवाओं को सामाजिक सुरक्षा, पूर्वानुमेय कॅरियर प्रगति एवं आर्थिक गरिमा से वंचित करता है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय असुरक्षा बनी रहती है।

शैक्षणिक मुद्रास्फीतिः उच्च शिक्षा के आक्रामक निजीकरण के कारण डिग्रियों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है, किंतु इसके साथ-साथ बाज़ार-प्रासंगिक कौशलों में समानांतर वृद्धि नहीं हो पाई है।

इसने शैक्षणिक योग्यताओं के मूल्य को गंभीर रूप से कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ विश्वविद्यालय की डिग्री अब आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देती।

संस्थागत क्षरण एवं समझौता-ग्रस्त योग्यता-आधारित व्यवस्था

खंडित सामाजिक अनुबंधः विशाल मध्यम एवं निम्न-मध्यम वर्गों के लिये प्रतियोगी परीक्षाएँ (जैसे NEET, UPSC एवं राज्य-स्तरीय आयोगों की परीक्षाएँ) सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) के लिये एकमात्र वैध माध्यम का प्रतिनिधित्व करती हैं।

प्रश्न-पत्र लीक, प्रतिरूप अभ्यर्थियों (Proxy Candidates) एवं भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब के लगातार बने रहने वाले संकट से योग्यता-आधारित राज्य व्यवस्था में लोगों का मूलभूत विश्वास कमज़ोर होता है।

राज्य की उदासीनता एवं विनियामक कमीः परीक्षा अवसंरचना पर प्रभावी नियामकीय निगरानी के अभाव तथा "कोचिंग हब" उद्योग के अनियंत्रित व्यावसायीकरण ने शिक्षा व्यवस्था को समान अवसर उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक संपदा के बजाय एक बहिष्कारी एवं लाभ-केंद्रित तंत्र में परिवर्तित कर दिया है।

समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक आयाम

संस्थागत अराजकता एवं सापेक्ष वंचनाः समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम के सिद्धांत के आधार पर, भारतीय युवा गंभीर अराजकता (Anomie) का अनुभव कर रहे हैं। यह ऐसी संरचनात्मक विघटन की स्थिति है, जो वित्तीय सफलता के सांस्कृतिक रूप से प्रतिष्ठित लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के लिये उपलब्ध संस्थागत साधनों के मध्य उत्पन्न असंगति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वैश्विक जीवन-शैलियों के निरंतर संपर्क ने सापेक्ष वंचना (Relative Deprivation) की भावनाओं को और अधिक तीव्र कर दिया है।

छात्र आत्महत्याओं की मौन महामारीः शैक्षणिक ऋण (Education Loans) एवं परीक्षा परिणामों में असफलता के पारस्परिक प्रभाव युवाओं पर अत्यधिक मानसिक दबाव डाल रहे हैं।

NCRB की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया (ADSI) 2024 रिपोर्ट के अनुसार, युवा एवं मध्यम आयु वर्ग (18-45 वर्ष) के वयस्क कुल आत्महत्याओं में 65.6% का योगदान करते हैं। [13,14,15]

चिंताजनक रूप से, वर्ष 2024 में छात्र आत्महत्याओं का अनुपात कुल मामलों का 8.5% तक पहुँच गया है, जिसके परिणामस्वरूप कोटा, चेन्नई और त्रिशूर जैसे अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी कोचिंग केंद्रों में दुखद घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि देखी जा रही है।

प्रतिभा पलायन (Brain Drain): प्रश्न-पत्र लीक, परीक्षा रद्द होने एवं भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब जैसी लगातार बनी रहने वाली संस्थागत विफलताएँ प्रतिभा पलायन को तीव्र कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप केवल उच्च-स्तरीय प्रतिभाएँ ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्गीय युवा भी स्थिर शिक्षा एवं रोज़गार अवसरों की तलाश में तेज़ी से विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत के मानवीय एवं वित्तीय पूंजी संसाधनों का ह्रास हो रहा है।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं लोकतांत्रिक विमुखता

हित समेकन की विफलताः पारंपरिक राजनीतिक संरचनाएँ मुख्य रूप से पहचान-आधारित राजनीति (जाति, धर्म एवं क्षेत्रवाद) तथा वृद्ध या ग्रामीण मतदाता वर्गों को लक्षित करने वाली कल्याणकारी लोकलुभावन नीतियों को प्राथमिकता देती हैं।

जेन ज़ी (Gen Z) की भौतिक चिंताएँ, जैसे आवास, मुद्रास्फीति एवं श्वेतपोश रोज़गार सृजन, मुख्यधारा के राजनीतिक एजेंडे में बड़े स्तर पर संबोधित नहीं की जाती हैं।

असहमति के लिये सीमित होते स्थानः जब संस्थागत माध्यम अपनी प्रभावशीलता खो देते हैं, तब युवा अपनी मांगों और असंतोष को व्यक्त करने के लिये सड़कों पर लामबंद होते हैं।[15,16]

हालाँकि राज्य की सामान्य प्रतिक्रिया तेज़ी से "शासन-आधारित पुलिसिंग" की ओर स्थानांतरित हो रही है, जिसमें रचनात्मक नीतिगत संवाद को प्रोत्साहित करने के स्थान पर प्रतिषेधात्मक आदेश (जैसे BNSS की धारा 163), इंटरनेट बंदी एवं डिजिटल निगरानी जैसे उपायों का प्रयोग किया जाता है। असहमति के इस अपराधीकरण (Criminalization of Dissent) से लोकतांत्रिक विमुखता और अधिक गहरी होती है।

विचार-विमर्श

"डेमोग्राफिक डिविडेंड" (जनसांख्यिकीय लाभांश) से "यूथ डिविडेंड" (युवा लाभांश) की ओर संक्रमणः फिनलैंड की युवा नीति के अनुरूप 'यूथ इन ऑल पॉलिसीज़' ढाँचे को अपनाया जाना चाहिये, जिसके अंतर्गत शिक्षा, रोज़गार, जलवायु और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रत्येक प्रमुख नीति में युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन अनिवार्य किया जाए।

नव-युगीन रोज़गार पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तारः समर्पित वित्तीय सहायता, स्टार्टअप इनक्यूबेशन और बौद्धिक संपदा (IP) समर्थन के माध्यम से ऑरेंज इकॉनमी (रचनात्मक उद्योग), क्रिएटर इकॉनमी, स्पोर्ट्स इकॉनमी, केयर इकॉनमी, स्पेस इकॉनमी और ग्रीन इकॉनमी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिससे पारंपरिक रोज़गार अवसरों से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में युवाओं के लिये अवसर सृजित हो सकें।

शासन में युवाओं की भागीदारी का संस्थागतकरणः सिंगापुर के नेशनल यूथ काउंसिल (National Youth Council) की तर्ज़ पर एक राष्ट्रीय युवा परिषद की स्थापना तथा युवा संसदों (Youth Parliaments) को सशक्त किया जाना चाहिये, ताकि युवाओं की भागीदारी केवल विरोध प्रदर्शनों तक सीमित न रहकर नीति निर्माण प्रक्रिया में संरचित रूप से सुनिश्चित हो सके।

योग्यता-आधारित व्यवस्था (Meritocracy) में विश्वास की पुनर्स्थापनाः सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (Fast-Track Special Courts - FTSCs) को पर्याप्त बुनियादी ढाँचे, न्यायिक जनशक्ति और तकनीकी सहायता के साथ सुदृढ़ किया जाना चाहिये, ताकि प्रश्न-पत्र लीक से संबंधित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हो सके और सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखी जा सके।[16,17,18]

साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को एक पूर्णतः स्वायत्त निकाय के रूप में सुदृढ़ करते हुए इसमें व्यापक संस्थागत सुधार किये जाने चाहिये। इसके अंतर्गत ब्लॉकचेन-आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन, ज़ीरो-ट्रस्ट परीक्षा आर्किटेक्चर, एआई-सक्षम निगरानी तथा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड डिजिटल परीक्षा अवसंरचना जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाया जाना चाहिये, ताकि योग्यता-आधारित परीक्षाओं की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता को मज़बूत करते हुए जनविश्वास को पुनः स्थापित किया जा सके।

चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR) के लिये शिक्षा का पुनर्कल्पनः उच्च शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उद्यमिता, जलवायु साक्षरता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, वित्तीय साक्षरता और डिज़ाइन थिंकिंग को समाहित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इसके साथ ही प्रत्येक डिग्री कार्यक्रम में शिक्षुता (Apprenticeship) को एक अनिवार्य एवं अभिन्न घटक के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय युवा कल्याण मिशन की स्थापनाः ऑस्ट्रेलिया के 'हेडस्पेस (Headspace)' मॉडल और यूनाइटेड किंगडम के छात्र मानसिक स्वास्थ्य ढाँचे से प्राप्त सीख के आधार पर विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों में परामर्श सेवाओं, कॅरियर मार्गदर्शन एवं आत्महत्या रोकथाम तंत्र को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिये।

सफलता के लिये बहुविध मार्ग (Multiple Pathways) विकसित करनाः 'परख' (PARAKH) के विस्तार, एकाधिक परीक्षा तिथियों/विंडोज की व्यवस्था, माइक्रो-क्रेडेंशियल (Micro-Credentials) की मान्यता तथा कौशल-आधारित भर्ती को बढ़ावा देकर एकल उच्च-दाँव वाली परीक्षाओं (Single High-Stakes Examinations) पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिये। यह जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में अपनाए गए बहुआयामी कौशल एवं मूल्यांकन मॉडल के अनुरूप होगा।

डिजिटल लोकतंत्र का लाभ उठानाः 'माईगव' (MyGov) को एक सुरक्षित एवं संवादात्मक डिजिटल परामर्श मंच के रूप में सुदृढ़ किया जाना चाहिये, जिससे सहभागी शासन (Participatory Governance) को बढ़ावा मिल सके। इसके माध्यम से युवा नागरिक नीतियों के प्रारूप, बजट और विधेयकों पर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें। यह ताइवान के vTaiwan सहभागी शासन मॉडल से प्रेरणा लेते हुए नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करेगा।[18,19]

नागरिक नवाचार और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देनाः 'युवा नवाचार मिशन' तथा नागरिक-तकनीक (Civic-Tech) इन्क्यूबेटरों की स्थापना की जानी चाहिये, जो प्रौद्योगिकी, सामाजिक उद्यमों और समुदाय-आधारित नवाचारों के माध्यम से युवाओं को सार्वजनिक समस्याओं के समाधान में सक्षम बनाएँ। यह अटल नवाचार मिशन (AIM) और स्टार्टअप इंडिया की दिशा के अनुरूप कार्य करेगा।

संपूर्ण-सरकार युवा रणनीति को अपनानाः यूरोपीय संघ की युवा रणनीति (2019-2027) के अनुरूप, शिक्षा की गुणवत्ता, रोज़गार, उद्यमिता, नागरिक सहभागिता, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल समावेशन जैसे क्षेत्रों में मापनीय लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय युवा रणनीति 2047 तैयार की जानी चाहिये।

रोज़गार-उन्मुख वृद्धि को बढ़ावा देनाः युवाओं के लिये व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजन के उद्देश्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के साथ-साथ कपड़ा, चमड़ा, जूते, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के लिये विशेष प्रोत्साहन उपायों को भी जोड़ा जाना चाहिये।

ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) जैसी पहलों के माध्यम से सुलभ एवं किफायती ऋण सुविधाओं तक पहुँच को सुदृढ़ करना, नियामकीय जटिलताओं को कम करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) से जोड़ना, जिससे गुणवत्तापूर्ण रोज़गार के अवसरों का विस्तार किया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रभावी एवं शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हुए गिग श्रमिकों (Gig Workers) के लिये कल्याण बोर्डों की स्थापना करना तथा स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा कवरेज एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

परिणाम

युवा आंदोलनों को मात्र असहमति (Dissent) के प्रकटीकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये, बल्कि उन्हें लोकतंत्र के प्रभावी प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये। युवाओं की आकांक्षाओं, नवाचार क्षमता और नागरिक सहभागिता की ऊर्जा का प्रभावी उपयोग यह निर्धारित करेगा कि भारत अपनी जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता को वास्तविक युवा लाभांश में किस प्रकार परिवर्तित करता है तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता है। रत में हाल ही में हुए युवा आंदोलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कुछ लोकप्रिय नारों में ऐसे अपशब्द और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें अधिकांश भारतीय दोहराने से भी हिचकिचाते हैं। इन नारों ने न केवल पुरानी पीढ़ी को, बल्कि कुछ युवा पीढ़ी के सदस्यों, साथ ही नागरिक समाज के अनुभवी सदस्यों, स्वतंत्र मीडिया और प्रगतिशील अधिकार आंदोलनों के नेताओं को भी चौंका दिया, जो विरोध प्रदर्शन की भाषा में एक निश्चित शालीनता और गंभीरता के आदी हैं।

एक लोकप्रिय नारे में हिंदी शब्द "कड़वा" और मराठी शब्द "दलाल" का तुकबंदी किया गया था: "नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला भड़वा है" ("नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी दलाल है")। अन्य नारों में लिंग और नितंबों के लिए अश्लील हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया था। अंग्रेजी शब्द "तानाशाह" पर भी कुछ भद्दा व्यंग्य देखने को मिला। 20 जुलाई को हुई पुलिस बर्बरता के बाद, शहर के केंद्रीय जिले के आसपास की दीवारों और पुलिस बैरिकेड्स पर अपशब्दों के भित्तिचित्र दिखाई दिए।

कुछ प्रदर्शनकारियों ने मोदी का मज़ाक उड़ाने के लिए धर्म और नैतिक कर्तव्य पर संस्कृत श्लोक का पाठ करते हुए एक ऑडियो भी चलाया। उनके अनुसार, संस्कृत वाक्यांश "लवणेन भोज्यम" ("नमक के कारण भोजन स्वादिष्ट होता है") का उनका उच्चारण लिंग के लिए एक अश्लील शब्द जैसा लग रहा था। इंस्टाग्राम पर कुछ वर्षों से लोकप्रिय यह मीम, कई अन्य पुराने और नए मीम्स के साथ सड़कों पर भी पहुंच गया।[19]

हालिया विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत व्यंग्यात्मक संगठन 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने की थी। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सोशल मीडिया ट्रोल नेटवर्क और सरकार की विचारधारा का पालन करने वाले मुख्यधारा के भारतीय मीडिया ने पहले भी मोदी सरकार के प्रदर्शनकारियों और आलोचकों को बदनाम किया है, लेकिन इस आंदोलन को विदेशी एजेंटों की साजिश के रूप में चित्रित करने में विफल रहे, क्योंकि अधिकांश प्रदर्शनकारी मुख्यधारा के हिंदू मध्यम वर्ग से थे, जो भाजपा का मुख्य समर्थक आधार है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के बाद ही, जो सत्ता में एक दशक बिताने के बाद मोदी की सावधानीपूर्वक गढ़ी गई छवि को हुए नुकसान को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम था, हमले की एक नई रणनीति सामने आई: आंदोलन के नारों में, विशेष रूप से युवा महिलाओं द्वारा, मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपशब्दों के आधार पर आंदोलन को बदनाम करना।

देश के केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड (जिसे सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है) के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पाती ने X पर एक पोस्ट में "लिंग-भेदभावपूर्ण अपशब्दों के प्रयोग" का मुद्दा उठाया। पूर्व राजनयिक कंवल सिबल ने भी ऐसा ही किया, जिन्होंने मोदी के खिलाफ "युवा लड़कियों" द्वारा कही जा रही बातों पर आपत्ति जताई – उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग "केवल सबसे असभ्य पुरुष ही कर सकते हैं।"

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने अपशब्दों के प्रयोग के लिए "युवा हिंदू महिलाओं" को निशाना बनाते हुए उन्हें "गटर पीढ़ी" बताया। "बेंड इट लाइक बेकहम" और "सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक" जैसी फिल्मों में काम कर चुके दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने मोदी के "अपमान और अनादर" पर दुख व्यक्त किया।

सरकार नारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से पोस्ट हटवाने के लिए ऑनलाइन कानूनों का इस्तेमाल कर रही है और देश के विभिन्न हिस्सों में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज करा रही है। इस बीच, भाजपा समर्थक प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते हुए लोगों की तस्वीरें ऑनलाइन प्रसारित कर रहे हैं, ताकि उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक की जा सके। कल, दिल्ली के उपनगर नोएडा में पुलिस ने 25 वर्षीय एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया, जब मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गए।

समाज के विभिन्न वर्ग इस अशिष्टता और मोदी के प्रति निर्देशित आक्रोश से जूझ रहे हैं, वहीं इसकी स्पष्टता ने विभाजन पैदा कर दिया है, जिससे सार्वजनिक रूप से क्या कहा जा सकता है और किसे कहने का अधिकार है, इस पर पीढ़ीगत और राजनीतिक मतभेद उजागर हो गए हैं।

युवाओं के लिए, गाली-गलौज करना स्वाभाविक, यहाँ तक कि हास्यास्पद भी लग सकता है; वहीं, वरिष्ठ पीढ़ी के लिए यह शर्म और आक्रोश से भरा हुआ है। इन दोनों के बीच में मिलेनियल्स हैं, जो इस पूरे सांस्कृतिक बदलाव से काफी खुश हैं।

पहले सार्वजनिक रूप से अपशब्द बोलना सभी वर्गों के पुरुषों का विशेषाधिकार हुआ करता था और इसे मर्दानगी का प्रतीक माना जाता था। लेकिन अब महिलाएं भी अपशब्द बोलने और गाली देने में संकोच नहीं करतीं।

निष्कर्ष

राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार मोदी की भाषा में भी एक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। 2012 में, उन्होंने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर (जिनका 2014 में निधन हो गया) का मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें "50 करोड़ रुपये की प्रेमिका" कहा था। उन्होंने सोनिया गांधी को "जर्सी गाय" कहकर उनके इतालवी मूल पर कटाक्ष किया और उन्हें "कांग्रेस पार्टी की विधवा" भी कहा। उनके पति, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में हत्या कर दी गई थी।

2023 में, भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी – जिन्होंने बाद में दिल्ली की एक सड़क की तुलना प्रियंका गांधी के गालों से की थी – ने अपने मुस्लिम सहकर्मी को "आतंकवादी" और "दलाल" कहा और संसद में खतना किए हुए व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि उनके बगल में बैठे भाजपा के दो पूर्व मंत्री हंस रहे थे।

मीडिया को दिए गए साक्षात्कारों में, हाल के विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाली युवा महिलाओं ने बताया कि वे बचपन से ही दक्षिणपंथी नेताओं और टीवी समाचार एंकरों को असंतुषों, विपक्षी नेताओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनती आ रही हैं।

भास्कर ने कहा, "उस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपशब्दों के मुद्दे पर नैतिक रुख अपनाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने ही इस संस्कृति को जन्म दिया है।"[19]

संदर्भ

1. "बांग्लादेश के छात्रों ने विश्व की पहली जेनरेशन जेड क्रांति कैसे की?" . द इंडिपेंडेंट . 7 अगस्त 2024. मूल लेख 4 नवंबर 2025 को संग्रहित किया गया ।
2. यहां जाएं: रेगन, हेलेन (6 अगस्त 2024)। "बांग्लादेश की 'जेनरेशन जेड क्रांति' ने एक अनुभवी नेता को सत्ता से हटा दिया। वे सड़कों पर क्यों उतरे और अब आगे क्या होगा?" । सीएनएन । मूल लेख 6 अगस्त 2024 को संग्रहित किया गया ।
3. यहां जाएं: पॉल, रूमा; दास, कृष्णा एन.; दास, कृष्णा एन. (6 अगस्त 2024)। "प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के अभियान की छात्र नेता नाहिद इस्लाम कौन हैं?" । रॉयटर्स । मूल लेख 6 अगस्त 2024 को संग्रहित किया गया ।
4. यहां जाएं: चौधरी, शमीम। "बांग्लादेश के छात्रों और पहली पीढ़ी की क्रांति को समर्पित एक रचना" । द न्यू अरब । मूल प्रकाशन 23 अगस्त 2024 को संग्रहित किया गया ।
5. सिंह, आनंद (11 सितंबर 2025)। "क्या यह एशियाई वसंत है? क्या इसमें अरब वसंत से समानताएं हैं?" । इंडिया टुडे । मूल प्रकाशन 11 सितंबर 2025 को संग्रहित किया गया । 19 सितंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया ।
6. यहां जाएं: "राय | अरब स्प्रिंग से एशियाई विद्रोह तक" . kathmandupost.com . मूल रूप से 19 सितंबर 2025 को संग्रहीत । 19 सितंबर 2025 को पुनः प्राप्त ।
7. सुफियान, अबू (15 अगस्त 2024)। "दक्षिण एशिया में अरब स्प्रिंग का प्रभाव: श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद, अगला पड़ाव? - संपादकीय"। यूरेशिया रिव्यू । मूल से 2 अक्टूबर 2025 को संग्रहित । 19 सितंबर 2025 को पुनः प्राप्त ।
8. यहां जाएं: "राय | एशिया में नेतृत्वहीन और आपस में जुड़ी हुई पीढ़ी सत्ता संभाल रही है" । 19 सितंबर 2025। मूल लेख 19 सितंबर 2025 को संग्रहित किया गया । 19 सितंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया ।
9. यहां जाएं: शर्मा, यशराज। "नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका: क्या दक्षिण एशिया जनरेशन जेड की क्रांतियों के लिए उपजाऊ है?" । अल जज़ीरा । मूल प्रकाशन 16 सितंबर 2025 को संग्रहित किया गया । 21 सितंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया ।
10. साल्वे, प्रियंका; मुरली, रक्षा (23 जुलाई 2026)। "भारत की 'तिलचट्टा पार्टी' के नेतृत्व में जनरेशन Z के विरोध प्रदर्शन मोदी के नेतृत्व की परीक्षा ले रहे हैं" । सीएनबीसी । मूल से 23 जुलाई 2026 को संग्रहीत । 23 जुलाई 2026 को पुनः प्राप्त ।

11. कौशल, श्रुति (23 जुलाई 2026)। "'मोदी जी, कृपया हमसे संबंध तोड़ लीजिए': जनरेशन Z के विरोध प्रदर्शन का तरीका भले ही गैर-गंभीर लगे, लेकिन इसका प्रभाव कम नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस । मूल लेख 23 जुलाई 2026 को संग्रहित किया गया । 23 जुलाई 2026 को पुनः प्राप्त किया गया ।
12. "दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच 'निराशाजनक भविष्य' के खिलाफ जनरेशन-जेड का विद्रोह" । ब्लूमबर्ग डॉट कॉम । मूल लेख 27 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया था । 31 मार्च 2026 को पुनः प्राप्त किया गया ।
13. "बांग्लादेश के छात्रों ने राजनीति में बदलाव लाने के लिए नई पार्टी का शुभारंभ किया" । डॉयचे वेले । 28 फरवरी 2025। मूल लेख 28 फरवरी 2025 को संग्रहित किया गया । 28 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त किया गया ।
14. दास, कृष्णा एन.; अगरवाला, तोरा (9 फरवरी 2026)। "बांग्लादेश में दुनिया का पहला जेनरेशन जेड-प्रेरित चुनाव" । रॉयटर्स ।
15. चौधरी, जिया; पॉल, रूमा; एन. दास, कृष्णा। "जेनरेशन जेड के विद्रोह के बाद, बांग्लादेश के चुनाव ने युवा शक्ति की सीमाओं को दिखाया" । रॉयटर्स ।
16. बीच, हन्ना (19 अप्रैल 2026)। "दुनिया भर में जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों का क्या हाल रहा है" । द न्यूयॉर्क टाइम्स । ISSN 0362-4331 । 20 अप्रैल 2026 को प्राप्त किया गया ।
17. यहां जाएं: कार्नेगी, मेगन (8 अगस्त 2022)। "जेन ज़ेड: युवा लोग सक्रियता को कैसे बदल रहे हैं" । बीबीसी न्यूज़ । मूल से 7 अगस्त 2022 को संग्रहीत । 8 अक्टूबर 2025 को पुनः प्राप्त ।
18. "ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर" . कार्नेगी एंडॉमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस . 31 मार्च 2026 को प्राप्त किया गया ।
19. किमाथी, शेरोन किट्स; किमाथी, शेरोन किट्स (2 अक्टूबर 2025)। "सतत परिवर्तन: जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में फैल रहे हैं" । रॉयटर्स । मूल से 5 अक्टूबर 2025 को संग्रहीत । 3 अक्टूबर 2025 को पुनः प्राप्त ।